

प्रेषक,

बी०एम०मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 10 मार्च, 2017

विषय:- जनपद चम्पावत में "एकीकृत सहकारी विकास परियोजना" हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या-490/XXVII-1/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016, 26 जुलाई, 2016 व 20 सितम्बर, 2016 के क्रम में आपके पत्र संख्या-6408/नियो०/आई०सी० डी०पी०-चम्पावत /2016-17 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, चम्पावत के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹59,00,000/- (रुपये उनसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (1) व्यय के संबंध में वित्त विभाग के आदेश संख्या-490/XXVII-1/2016, दिनांक 31 मार्च 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति से शासन को त्रैमासिक रूप से अवगत कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हो जाए और उसे कोषागार के संगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करा दिया जाए।
- (3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तों/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय-समय पर निर्गत शर्तों के अनुरूप नियंत्रित होगी।
- (5) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की होगी।
- (6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करानी होगी और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।
- (7) पैरा-1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाई जायेगी। परियोजना का नियमानुसार लेखा परीक्षण, मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

(8). उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम" द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उक्त धनराशि निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित परियोजना को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामे डाला जायेगा:-

अनुदान संख्या-18

लेखाशीर्षक	(धनराशि ₹ में)
स्वीकृत धनराशि	
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 00-200-अन्य निवेश 03-समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00-30-निवेश/ ऋण।	55,63,000.00
6425-सहकारिता के लिए कर्ज-आयोजनागत 00-800-अन्य कर्ज 04-एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00-30-निवेश/ ऋण।	3,37,000.00
योग-	(उनसठ लाख रुपये मात्र)
	59,00,000.00

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-490/XXVII-1/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016, 26 जुलाई, 2016 व 20 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-आई0डी0 मूल रूप में।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या:-2410 (1)/XIV-1/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराँय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4-सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु।
3. मण्डलायुक्त, कुमाँयू, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. जिला निबंधक, सहकारी समितियां, चम्पावत।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-4/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुनील सिंह)
उप सचिव।